



209

न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल ग्वालियर ४ म.प्र. ४

श्री. श्री. राजनी वि. प्र. ४
दाय आज दि. 16/8/16 को
प्रस्तुत
वकास
कलक और 16-8-16
सन्तुलन पण्डल म.प्र. ग्वालियर

जि.प्र. 2751 II/16

1. दुर्गाप्रसाद तनय विन्दा अहिरवार
सा. पड़रहा तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.
 2. रामनाल तनय श्यामनाल ब्राम्हण
निवासी पन्ना रोड, छतरपुर म.प्र.
 3. श्रीमति सरिता पत्नि सियाराम वर्मा
 4. श्रीमति शिला पत्नि रामकुमार वर्मा
- दोनों निवासी अम्बेडकर नगर, पन्ना रोड, छतरपुर म.प्र.

.. निगरानी कर्ता गिण

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार महोदय छतरपुर के रा.प्र. क्र. 37/अ63/11/12 में पारित आदेश दिनांक 16.8.13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानी कर्ता गिण की ओर से निम्न प्रार्थना है -

1:-

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमना प्रसाद तनय सुखन्दी पाठक को दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत पात्रता होने के आधार पर आराजी नंबर 68/1 रकवा 1.58 7 हेक्टेयर मौजा गुरैया तह. व जिला छतरपुर के प्र. क्र. - 60/अ-19/1987-88 आदेश दिनांक 4.4.1988 के तहत भूमि स्वामी हक पर पददा प्राप्त हुआ था । उक्त आशय की प्रविष्टि खसरा पाचिशाला में वर्ष 1987-88 पर दर्ज है ।

Handwritten signature

Handwritten signature ..2..

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2751-एक/16

जिला -छतरपुर

स्थान दिनांक	तथा	कार्यवाही तथा आदेश
16.8.16		<p>आवेदकगणा की और से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक की और से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित. उभय पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा निगरानी की ग्राह्यता एवं धारा-5 के आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये। धारा-5 का आवेदन समाधान कारक होने के कारण मान्य किया जाता है।</p> <p>2- यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2013 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 68/1 रकबा 1.587 हेक्टेयर स्थित मौजा गुरैया तहसील व जिला छतरपुर का पट्टा राजस्व प्रकरण क्रमांक 60/अ-19/1987-88 में मध्यप्रदेश दखल रहित भूमि अधिनियम 1984 के अन्तर्गत दिनांक 4-4-1988 को जमना प्रसाद के हित में हुआ था. उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई थी उक्त पट्टे की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी. पंचायत चुनाव में रंजित के कारण आवेदकों को परेञ्चान करने के लिये गांव के ही एक व्यक्ति ने अभिलेख सुधार हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु समझौता हो जाने के कारण तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 26-12-2012 को प्रकरण वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. आवेदकगण पट्टाधारी जमना प्रसाद से उक्त भूमि</p>

प्राप्त
अभिभाषक
आदि के
हस्ताक्षर

B
AK

AK

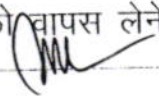
-2- प्रकरण क्रमांक निगरानी 2751-एक/16

पंजीकृत विक्रय पत्र के जर्ने दिनांक 18-07-2012 को क्रय की है। क्रय करने के पश्चात आवेदकगण का नामान्तरण पंजी क्रमांक 66 वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 29-9-2012 को किया गया। आवेदकगण को तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरण की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। तहसील न्यायालय ने प्रकरण वापसी के आवेदन पत्र पर कोई विचार किये बिना तथा आवेदकगण को कोई सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना विवादित आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण आदेश पारित करने के दिनांक 16-08-21013 को भूमि के हितबद्ध एवं आक्षयक पक्षकार थे क्योंकि उनका नाम राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट हो चुका था। तहसील न्यायालय को 1984 के अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार द्वारा विवादित आदेश द्वारा भूमि को मध्यप्रदेश शासन घोषित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक एक सदभाविक क्रेता है तथा पट्टाधारी जमना प्रसाद को भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस कारण से तहसीलदार का विवादित आदेश दिनांक 16-08-2013 अवैध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाये।

3-शासकीय पैनल अभिभाषक ने तहसीलदार की कार्यवाही एवं आदेश को स्थिर रखने एवं निगरानी निरस्त करने की मांग की।

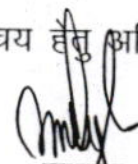
4- उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन करने के पश्चात में यह पाता हूँ कि प्रकरण में विवादित भूमि का पट्टा जमना प्रसाद को वर्ष 1988 में दखलरहित भूमि अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया गया था। उक्त पट्टे के विरुद्ध लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रारम्भ की गयी कार्यवाही में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत

R
S



किया गया था. प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण का नाम नामान्तरण पंजी क्रमांक -66 में पारित आदेश दिनांक 29-9-2012 को किया गया था को आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 16-08-2013 को भूमि को शासन की घोषित किया गया है, इस कारण से तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है. प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने वर्ष 1988 में हुए पट्टे को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के निरस्त करने में एवं भूमि को शासकीय घोषित करने में अपने विचाराधिकार उल्लंघन किया है. इस कारण से भी तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होना पाता हूँ, प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि पट्टाधारी को भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई थी उसके द्वारा उक्त भूमि को 10 वर्ष के फ़्वात विक्रय किया गया है जिससे यह प्रमाणित पाता हूँ कि उसके द्वारा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. विधि का यह सर्वमान्य नियम है कि क्रेता को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो विक्रेता को थे. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2013 निरस्त किया जाता है. तथा नामान्तरण पंजी क्रमांक 66 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2012 के अनुसार आवेदकगण का नामान्तरण आदेश स्थिर रखा जाता है, तथा आवेदकगण का नाम उक्त भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं. तदनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

B
दी


सदस्य